भारत ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ी मजबूत लड़ाई

अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संदेश

नई दिल्ली, 26 जून. अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने 'नशा मुक्त भारत' का संदेश दिया है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ड्रग्स के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है.

गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ड्रग्स के खिलाफ हमारी राष्ट्रीय लड़ाई में शामिल सभी योद्धाओं को शुभकामनाएं. अमित शाह ने आगे लिखा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ड्रग्स के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है. इसके तहत नार्को-कार्टेल्स का कठोरता से सफाया किया जा रहा है और प्रभावित लोगों का उचित देखभाल और सहानुभूति के साथ इलाज किया गया है. यह दिन हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग्स से बचाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करे.

स्वस्थ जीवनशैली के प्रति लोगों को जागरूक करें : धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नशा सिर्फ व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके परिवार, समाज और राज्य की उन्नति में भी गंभीर बाधा उत्पन्न करता है. उन्होंने कहा, हमारा संकल्प देवभूमि उत्तराखंड को नशे के अभिशाप से मुक्त कर स्वस्थ, जागरूक और सशक्त युवाशक्ति के माध्यम से एक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है. आइए, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर हम सभी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज में व्यापक जन जागरूकता फैलाने एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति लोगों को प्रेरित करने का संकल्प लें.

नशा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास में बाधा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, नशा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास में बाधा है. यह व्यक्ति की सोच, स्वास्थ्य और भविष्य तीनों को कमजोर करता है. आइए, आज 'अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस' के अवसर पर नशा-मुक्त समाज की दिशा में हर व्यक्ति को जागरूक कर एक बेहतर कल की ओर बढ़ें. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर लोगों से अपील करते हुए कहा, आइए, हम सभी नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लें.

गांजा तस्करी का बड़ा भंडाफोड़

लखनऊ, 26 जून. श्रावस्ती जिले की मल्हीपुर पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस सेल के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. पुलिस ने 2.365 किलोग्राम गांजा, 19,82,645 रुपये भारतीय नकद, 320 रुपये नेपाली मुद्रा, एक नेपाली पासपोर्ट और गांजा पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया है. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1.18 लाख रुपये बताई गई है. यह कार्रवाई मोहर्रम पर्व के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान की गई. प्रभारी निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह अपनी टीम के साथ कर्बला तिराहे पर मौजूद थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि जमुनहा गांव में एक परचून की दुकान की आड़ में अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान के बाहर बैठे शिवप्रसाद को पकड़ लिया.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा

- अच्छे परिवारों के बच्चे ऐसा क्यों : फडणवीस
- सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले केतन के पिता

मुंबई, 26 जून. पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद चौंकाने वाली है और इसे केवल हत्या के एक मामले के रूप में नहीं, बल्कि समाज की बदलती मानसिकता के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा, पढ़े-लिखे और अच्छे परिवारों के बच्चे ऐसी हिंसक सोच क्यों अपना लेते हैं. यह हम सभी के लिए गंभीर चिंतन का विषय है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

मुलाकात के दौरान केतन अग्रवाल के पिता ने मुख्यमंत्री से दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की. उन्होंने कहा कि उनके बेटे की नृशंस हत्या ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है और उन्हें न्याय तभी मिलेगा जब आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले. मामले से जुड़े परिवारों की ओर से कई भावनात्मक दावे भी सामने आए हैं. केतन की हत्या की आरोपी बताई जा रही सिया के संबंध में उसके परिवार की ओर से यह दावा किया गया कि उसकी कथित करतूतों से आहत होकर उसके पिता को हार्ट अटैक आया. वहीं, उसकी मां ने मीडिया से बातचीत में कथित रूप से कहा कि यदि उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी कठोरतम सजा मिलनी चाहिए. इसी तरह, कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि कथित हत्या की साजिश के पहले दो प्रयास विफल होने के बाद सिया ने अपने साथियों को फटकार लगाई थी.

एफआईआर केवल दिखावे के लिए की गई

लखनऊ, 26 जून. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजा-अर्चना की. दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए.

बड़े लोग बचाए जा रहे : केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर केवल औपचारिकता निभाने और लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है. उनका आरोप था कि इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता केवल कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों के भरोसे नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि यदि करोड़ों रुपये के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए उच्च स्तर तक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि असली दोषियों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों को आगे किया जा रहा है. केजरीवाल ने कहा कि जनता जानना चाहती है कि आखिर इतने बड़े मामले में जवाबदेही किसकी है और जांच की दिशा क्या है. उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके.

अपने संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए वहां चढ़ाए जाने वाले दान और चढ़ावे का प्रबंधन पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए. उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थानों में लोगों का विश्वास सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. केजरीवाल के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है, जबकि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है.

प. बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकी साजिश

एनआईए ने 11 आरोपियों पर आरोप पत्र दाखिल किया

नई दिल्ली, 26 जून. प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बंगलादेश (जेएमबी) के 11 संदिग्धों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में असम में गुवाहाटी की विशेष एनआईए अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया है.

एनआईए की जांच से पता चला कि इन आरोपियों ने जेबीएम के ही एक और रूप इमाम महमूदूर काफिला (आईएमके) की साजिश में सक्रिय रूप से साथ दिया था। इस साजिश का मकसद पश्चिम बंगाल समेत असम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में इस आतंकवादी संगठन की विचारधारा फैलाना था. आतंकवाद विरोधी संगठन की जांच से पता चला कि जेबीएम के वरिष्ठ सदस्य इमाम

- हबीबुल्लाह ने भारत में आईएमके की स्थापना की थी

महमूद हबीबुल्लाह ने भारतीय धरती पर प्रतिबंधित संगठन के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए आईएमके की स्थापना की थी. जांच में आपत्तिजनक दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल रिकॉर्ड की एक श्रृंखला का पता लगा है.

रिश्वत लेने के आरोप में पीएनबी मैनेजर गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 जून. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आगरा में तैनात पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एक प्रबंधक को लगभग 19 सोलर पैनल कर्ज की फाइलों को आगे बढ़ाने और मंजूर करने के एवज में कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने शुक्रवार को बताया कि एक निजी कंपनी के कर्मचारी की शिकायत के आधार पर 25 जून को आरोपी प्रबंधक प्रवीण यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया था. सीबीआई के अनुसार, यादव ने करीब 19 सोलर पैनल कर्ज की फाइलों को प्रोसेस और क्लियर करने के लिए कथित तौर पर प्रति फाइल 7,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

पत्नी पति की संपत्ति नहीं

भुवनेश्वर, 26 जून. उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को रेखांकित करते हुए कहा कि पत्नी को पति की संपत्ति नहीं माना जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि हर बालिग महिला को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपना निवास स्थान और जीवन से जुड़े फैसले स्वयं ले सके.

मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति मुरारी रमन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक हेबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान की. याचिका में एक पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी का अपहरण कर उसे अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है और उसे अदालत के समक्ष पेश कराया जाए. सुनवाई के दौरान जब महिला अदालत के समक्ष पेश हुई तो उसने स्पष्ट रूप से बताया कि वह अपनी इच्छा से ससुराल छोड़कर गई है और किसी के अवैध कब्जे या दबाव में नहीं है. महिला के इस बयान के बाद अदालत ने माना कि यह अपहरण या अवैध हिरासत का मामला नहीं

उड़ीसा हाई कोर्ट का अहम फैसला

है. खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई बालिग महिला वैवाहिक जीवन में उत्पीड़न, मतभेद या किसी अन्य व्यक्तिगत कारण से अलग रहने का निर्णय लेती है तो उसे जबरन पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. अदालत ने यह भी कहा कि किसी महिला की स्वतंत्र इच्छा और उसकी गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए.

एक नजर में

तुर्की में 100 से अधिक संदिग्ध गिरफ्तार

अंकारा. नाटो शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक अभियान के तहत तुर्की की राजधानी अंकारा में आतंकवादी संगठनों से संबंध होने के संदेह में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की की रिपोर्ट के अनुसार, यहां सात-आठ जुलाई को नाटो राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन होना तय हुआ है। गुरुवार को रिपोर्ट दी है कि अदालत के आदेश पर 103 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 26 अन्य को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। अंकारा के गवर्नर ने नाटो शिखर सम्मेलन से पहले अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किये हैं। इसके बाद 23 जून को इस अभियान को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस जांच में कुल 225 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

कांगो में इबोला से मरने वालों की संख्या 300 के पार

इथियोपिया. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो (डीआरसी) में इबोला से मरने वालों की संख्या 300 से ज़्यादा हो गई है और इसके 1,155 मामलों की पुष्टि की गयी है. डीआरसी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी. मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा, यह महामारी इतुरी, नॉर्थ किवु और साउथ किवु प्रांतों में अभी भी फैली हुई है जिसमें 1,155 कन्फर्म मामले और 304 मौतें शामिल हैं.

पासपोर्ट शुल्क वृद्धि पर कांग्रेस ने की केंद्र की आलोचना

नयी दिल्ली, 26 जून. कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक जुलाई से लागू होने वाली पासपोर्ट शुल्क वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे आम जनता पर 'महंगाई की नई किस्त' करार दिया है.

शुक्रवार को जारी बयान में श्री सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाना 2,000 रुपये तक महंगा कर दिया है. उनके अनुसार 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट की सामान्य श्रेणी की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये तथा तत्काल श्रेणी की फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर

रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले- 'महंगाई की नई किस्त'

5,000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये और तत्काल शुल्क 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है।

राधाकृष्णन आज से कर्नाटक की यात्रा पर

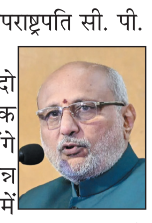

नई दिल्ली. उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन शनिवार को दो दिन की कर्नाटक यात्रा पर जायेंगे जहां वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. उप राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन शनिवार को बेंगलुरु में नादप्रभु श्री केम्पेगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह में शामिल होंगे. रविवार को वह बेंगलुरु में ही राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के स्थापना दिवस और नशा मुक्त भारत कॉन्क्लेव में भाग लेंगे.

गुजरात में ऊर्जा बचत अभियान शुरू

सरकारी दफ्तरों में बिजली बचत के सख्त निर्देश जारी

अहमदाबाद, 26 जून. गुजरात सरकार ने ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में बिजली बचत के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग और सड़क एवं भवन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब सभी सरकारी कार्यालयों में

एयर कंडीशनर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर रखना अनिवार्य होगा. यह निर्णय भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मानकों के अनुरूप लिया गया है.

सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि कार्यालय समय समाप्त होने के बाद, सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाशों में लाइट, पंखे, एसी, कंप्यूटर और अन्य विद्युत उपकरण पूरी तरह बंद रखे जाएं. जो अधिकारी अवकाश पर हों या फील्ड ड्यूटी पर हों, उनके कमरों में भी बिजली के उपकरण बंद रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी.

हस्तियों के ट्वीट

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही मैं सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिबद्धता से विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से अन्नदाताओं के कल्याण, आत्मनिर्भरता और समृद्धि का मार्ग निरंतर सशक्त हो रहा है.

बराक ओबामा हाल ही मैं सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा किमेरी बहन माया और मुझ पर हमारी माँ, ऐन डनहम का गहरा असर रहा है. माया को ओबामा प्रेसिडेंशियल सेंटर की झलक दिखाना—जिसमें हमारी माँ की याद में माया लिन की बनाई एक नई मूर्ति भी शामिल है—सचमुच बहुत खास अनुभव था.

आज का इतिहास

- 1759 : ब्रिटेन के सेना अधिकारी जनरल जेम्स वोल्फ ने क्यूबेक पर कब्जा जमाने की शुरुआत की.
- 1838 : राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म.
- 1867 : बैंक ऑफ कैलिफोर्निया का संचालन शुरू.
- 1893 : पंजाब के महाराज रंजीत सिंह का निधन.
- 1914 : अमेरिका ने इथोपिया के साथ वाणिज्य संधि पर हस्ताक्षर किये.
- 2008 : माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने अपने पद से इस्तीफा दिया.

दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन

नई दिल्ली, 26 जून. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर 28 और 29 जून को नई दिल्ली के पूसा स्थित भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में

- शिवराज सिंह की अध्यक्षता में होगा महाकुंभ

पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.

इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति विशेषज्ञ और विभिन्न योजनाओं से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे. सम्मेलन का मुख्य विषय 'विकसित ग्राम-विकसित भारत' रखा गया है. इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर गांवों के समग्र विकास के लिए साझा कार्ययोजना तैयार करना है. सम्मेलन में विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं, संसाधनों के बेहतर उपयोग और ग्रामीण विकास की नई रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा होगी.

दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सहित प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

प. बंगाल के सीएम ने रखा नए कानून का प्रस्ताव

अपराधियों की सात पीढ़ियां याद रखेंगी : सुवेंद

कोलकाता, 26 जून. पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार का दिन एक बड़े धमाके की तरह होगा. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी राज्य के 54 साल पुराने कानून में बदलाव करने जा रही है. एक ऐसा 'ब्रह्मास्त्र' लाने जा रहे हैं, जो अपराधियों की रीढ़ तोड़ देगा.

इस नए कानून को उत्तर प्रदेश के 'बुलडोजर मॉडल' से भी कई गुना अधिक घातक और सख्त माना जा रहा है. इसे लेकर पूरे बंगाल के गुंडा-बवालियों में अभी

गुंडों पर सख्त कानून की मांग
54 साल पुराने कानूनों की विदाई

से मौत का खौफ है. जानते हैं पूरी कहानी.

बंगाल राज्य सरकार1972 में बने कानून पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, 1972 उसमें संशोधन करने जा रही है. इसे 1972 में पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और उसी वर्ष राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू हुआ था. 1960 और 70 का दशक के दौर में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता, हिंसक आंदोलन और कानून-व्यवस्था की भारी समस्याएं थीं. सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने, उग्रवादी गतिविधियों को रोकने और अवैध हथियारों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार को विशेष शक्तियों की जरूरत थी, जिसके लिए यह कानून 1972 में लाया गया था. लेकिन अब बंगाल सरकार 'पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026' को विधानसभा में पेश करने जा रही है.

पटाक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 1957 की सेल डीड को दिया वैध करार

70 साल बाद आया जमीन विवाद का फैसला

नई दिल्ली, 26 जून. देश की न्यायिक व्यवस्था में लंबे समय तक चले भूमि विवादों में से एक का अब पटाक्षेप हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार के नरसीपुर कलां गांव की 15.5 बीघा जमीन से जुड़े करीब सात दशक पुराने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 1957 की सेल डीड को वैध करार दिया है।

शीर्ष अदालत के इस निर्णय के साथ चार पीढ़ियों से चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई और अपीलकर्ता परिवार को जमीन का वास्तविक मालिकाना अधिकार मिल गया। यह मामला 4 जून 1957 को हुई

जमीन की खरीद से शुरू हुआ था। शराफत अली के पूर्वजों ने सेल डीड के जरिए यह जमीन खरीदी थी, लेकिन वर्षों बाद राजस्व रिकॉर्ड और चकबंदी प्रक्रिया के दौरान स्वामित्व को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला धीरे-धीरे निचली अदालतों से होते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया शामिल थे, ने निचली अदालतों और हाईकोर्ट के पुराने फैसलों को पलटते हुए कहा कि पुराना बिक्री दस्तावेज पूरी तरह वैध है। अदालत ने माना कि जमीन पर अधिकार खरीदार पक्ष का ही है। मामले की सबसे खास बात यह रही कि जब यह विवाद शुरू हुआ था, तब फैसला सुनाने वाले दोनों न्यायाधीशों का जन्म भी नहीं हुआ था। सात दशक तक चली इस कानूनी लड़ाई में मूल पक्षकारों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अंतिम राहत मिली। यह विवाद म्यूटेशन, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून और चकबंदी प्रक्रिया से गुजरता हुआ देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न केवल एक परिवार की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा समाप्त की, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि वैध दस्तावेज और वास्तविक अधिकारों को केवल राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के आधार पर नकारा नहीं जा सकता।

आखिरी बार बता रहा हूं

मुंबई 26 जून. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में आयोजित पार्टी की समीक्षा बैठक में संगठन की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए

एमएनएस पदाधिकारियों को राज ठाकरे का अल्टीमेटम

पदाधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब काम में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को तत्काल सक्रिय होकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा.

एमएनएस प्रमुख ने कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन की मजबूती सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने, स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रहने और पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया. उन्होंने संकेत दिया कि अब निष्क्रिय पदाधिकारियों के प्रति सख्त रुख अपनाया जाएगा और संगठन में जवाबदेही तय की जाएगी. राज ठाकरे ने बैठक में यह भी कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर पदाधिकारी को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी.

बंगाल और छग सरकार का यूसीसी पर बड़ा कदम

नई दिल्ली. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है. पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के मंत्री शंकर घोष के बयान ने इस मुद्दे को नई सुर्खियों में ला दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यूसीसी को लेकर गंभीर है और इसे विधानसभा में पेश करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है. उनके अनुसार, यह कानून लागू होने पर राज्य की कानूनी व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा और सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होंगे. शंकर घोष ने इसे पश्चिम बंगाल के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है. उनका कहना है कि यूसीसी लागू होने से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे मामलों में समान कानून लागू होगा, जिससे न्याय व्यवस्था अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी.